

सम्पादकीय

राजनीतिक भंवर में परीक्षा प्रकरण

उत्तराखण्ड में एक सप्ताह पूर्व हुई स्थातक स्तरीय परीक्षा में भले ही कुछ लोगों की गिरफ्तारी हुई हो लेकिन इस प्रकरण को लेकर राजनीति का ग्राफ अब लगातार अपर उठ रहा है। इधर भारतीय जनता पार्टी ने अपने सभी विधायकों को मैदान में उतार दिया है जो कि अपने—अपने क्षेत्र में परीक्षाओं को लेकर सभी बातें सही होने का दावा करते फिर रहे हैं। हालांकि दूसरी तरफ कांग्रेस भी परीक्षाओं में धांधली को लेकर मुखर है और अब सरकार के पुतले फूंकने का काम कर रही है तो अब कांग्रेस ने परीक्षा निरस्त होने और सीधीआई जांच न होने की स्थिति में बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया है। यानी की रूपए है कि यह प्रकरण अब सरकार के गले की फाँस बन चुका है और अब तक किए गए सभी प्रयास छात्रों को मनाने में असफल साबित हुए हैं। इसी कड़ी में निर्दलीय विधायक खानपुर भी कूद पड़े हैं और उन्होंने पूरी परीक्षा प्रणाली की जांच के लिए सीधीआई जांच की तो मांग की ही है साथ ही विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए भी पत्र भेजा है। आने वाले दिनों में यह प्रकरण उत्तराखण्ड की राजनीति में काफी हांगामा पैदा करने वाला है तो वही दूसरी तरफ सरकार के मुखिया अभी भी खुद को युवाओं के साथ बात कर नकल माफियाओं पर नकल लगाने की बात कर रहे हैं। यह तो स्पष्ट है कि उत्तराखण्ड की परीक्षा प्रणालियों को लेकर प्रदेश का युवा भ्रम की स्थिति में है और अब उसे यह लगाने लगा है कि राज्य सरकार और आयोग किसी भी परीक्षा को निर्विवाद संपन्न कराने की स्थिति में नहीं है। सरकार के लिए युवाओं में पनपती यह सोच अच्छा सकते नहीं हैं खास तौर से उन परिस्थितियों में जबकि 2027 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि युवाओं और उनके अभिभावकों का यह रोष सरकार की तिगड़ी बनने से पहले ही उसे मैदान से बाहर कर दें। मुख्यमंत्री को तत्काल अपनी छवि के अनुरूप फैसला अब ले ही लेना चाहिए।

राहुल गांधी की गलत धारणा

भारत निर्वाचन आयोग ने नेता प्रतिष्ठ राहुल गांधी के गोटोरों के आयोग को खारिज कर दिया। अपनों पोर्ट में आयोग ने लिखा, किसी भी बोर्ड को अन्वेषित किसी शख्स द्वारा हटाया नहीं जा सकता, जैसा कि गांधी ने गलत धारणा बना रखी है। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के विरुद्ध नेता गांधी ने आयोग लगाया था कि मुख्य चुनाव अवृत्त जानेस बाहर बोर्ड चारों को संस्करण दे रहे हैं और कफी मतदाताओं को घटाने। जोड़ने में होने वाली थोखाधड़ी की हानि हो जानकारी है। एक बोर्ड के अवृत्त विधानसभा क्षेत्र में कम से कम छह बोर्ड चारों वाले विधायकों में कुछ इसी तरह की थोखाधड़ी का आयोग लगाया था। उनके अनुसार सोंप्लेवर का प्रयोग कर असली मतदाताओं का रूप लिया गया। गांधी ने बूथ लिवल के अधिकारी के चाचा का नाम हटाया जाने की भी चाची को। कुछ समय से विश्वासी दल दावा करते रहे हैं कि आयोग का साथ मिलकर मतदात सूची से फर्जी बोर्ड द्वारा/जोड़े का काम कर रहा है। चुनाव अवृत्त को लोकतंत्र के हर-फेर के सटीक प्रमाण नहीं मिले। आयोग निराशर नहीं हैं तो इन्हें खतरे की धूमी हो माना ही जाना चाहिए। आयोग को कीचड़ उत्तराने की बजाय अपनी खामियों को सुधारने के प्रति पारदर्शीतापूर्ण कदम उठाने नजर आना चाहिए।

